WRITTEN ANSWERS TO STARRED QUESTIONS

वस्त्र आयुक्त के कार्यालय के कार्यकरण के मूल्यांकन हेतु समिति की नियुक्ति

*282. श्री अनंतराव देवशंकर दवे : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने वस्त्र आयुक्त के कार्यालय के कार्यकरण का व्यापक मूल्यांकन करने के लिए एक सदस्यीय समिति की नियुक्ति की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त समिति का प्रतिवेदन कब तक प्राप्त हो जाने की संभावना है?

वस्त्र मंत्री (श्री आर०एल० जालप्पा) : (क) तथा (ख) जी हां, वस्त्र आयुक्त के कार्यालय के कार्यचालन का एक विस्तृत मूल्यांकन करने के लिए अप्रैल 1995 में श्री के०एन० अर्द्धनारीश्वरन की अध्यक्षता में एक सक-सदस्यीय समिति गठित की गई थी। समिति के विचारार्थ विषय निम्नानुसार थे:-

1. वस्त्र आयुक्त के कार्यालय की विद्यमान संगठनात्मक व्यवस्था का अध्ययन करना
2. वस्त्र आयुक्त के कार्यालय की विभिन्न शाखाओं तथा इसकी वर्तमान प्रांसगिकता की समीक्षा करना
3. वस्त्र आयुक्त के कार्यालय द्वारा किये जा रहे निर्धारित कार्यों की प्रभावकारिता का अध्ययन तथा उनके जारी रखने की आवश्यकता की जाँच करना
4. वस्त्र आयुक्त के कार्यालय के कार्यचालन की समग्र समीक्षा तथा उद्योग के विनियंत्रण तथा गैर-विनियमन की वर्तमान नीति के संदर्भ में इसकी भावी भूमिका के लिए सिफारिशें करना
5. वस्त्र उद्योग के विकास को सरल बनाने के रूप में वस्त्र आयुक्त के कार्यालय को पुन: अनुकूल बनाना
6. वस्त्र उद्योग के विभिन्न क्षेत्रों/मदों के संबंध में आंकड़ों के संग्रहण के तंत्र की समीक्षा करना तथा इसके सुधार के लिए उपायों का सुझाव देना
7. अन्य कोई मामला

(ग) समिति ने अपनी रिपोर्ट नवम्बर, 1995 में प्रस्तुत कर दी थी। तदन्तर, वस्त्र सचिव की अध्यक्षता में एक अधिकार-प्राप्त समिति ने इसका अध्ययन किया तथा रिपोर्ट में दिये गए निष्कर्षों के संबंध में सिफारिशें प्रस्तुत की। अधिकार प्राप्त समिति की सिफारिशों को सरकार द्वारा स्वीकार कर लिया गया है।

भारत-बंग्लादेश सीमा पर स्थित विदेशी अंत: क्षेत्र (इन्कलेव)

*285. श्री राम जेठमलानी : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि भारत-बंगलादेश सीमा पर 130 विदेशी अंत: क्षेत्र (इन्कलेव) जिनकी भूमि का क्षेत्रफल 2,650.35 एकड़ है, भारतीय सीमा में पड़ते हैं, लेकिन इस क्षेत्र के बंगलादेश सीमा क्षेत्र से घिरा होने के कारण वहां कोई भारतीय मतदाता नहीं है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में तथ्य क्या हैं;

(ग) क्या ये विदेशी अंत: क्षेत्र (इन्क्लेव) देश के विभिन्न राज्यों के अंश के रूप में शामिल कर लिये गये हैं; और

(घ) यदि हां, तो ये विदेशी अंत: क्षेत्र किस-किस भारतीय राज्य के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन हैं?

गृह मंत्री (श्री इन्द्रजीत गुप्त) : (क) और (ख) उपलब्ध जानकारी के अनुसार, बंगलादेश में 119 विनिमेय भारतीय अन्त: क्षेत्र हैं (लगभग 17000 एकड़) जबकि भारत में बंगलादेश के 72 विनिमेय अन्त: क्षेत्र हैं (लगभग 7000 एकड़)। कोई भी पक्ष, दूसरे देश में अवस्थित अपने अन्त: क्षेत्रों पर नियंत्रण रखने में सफल नहीं रहा है। बंगलादेश के अंदर पड़ने वाले अन्त: क्षेत्रों पर सरकार का कोई प्रशासनिक नियंत्रण अथवा पहुंच नहीं है और इसी से वहां के निवासियों को मताधिकार देना संभव नहीं हुआ है। अन्त: क्षेत्रों का विनिमय, भारत-बंगलादेश भू-सीमा समझौता, 1974 के अनुसार बंगलादेश के साथ सीमांकन से सीधा जुड़ा हुआ है और सीमांकन के बाद भारत द्वारा इस सीमांकन की पुष्टि के पश्चात अवश्य ही इन क्षेत्रों का विनिमय होगा।

(ग) और (घ) बंगलादेश के भीतर स्थित भारतीय अन्त: क्षेत्र, पश्चिम बंगाल राज्य का हिस्सा हैं।